# भारत में बाल पोषण की स्थिति में सुधार

डॉ. अरविंद गुप्ते

किसी बच्चे का वज़न और लम्बाई सामान्य से कम होना कुपोषण का सूचक है। लम्बाई कम होने को रुद्ध विकास (stunting) कहते हैं। इस समस्या का कारण बचपन में पर्याप्त पोषण न मिलना है। सन 2005-2006 में किए गए देशव्यापी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) में यह पाया गया था कि पूरे संसार में पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में सबसे अधिक कुपोषण भारत में पाया जाता है। देश के 42.5 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए थे। गौरतलब है कि अफ्रीका के लिए यह औसत केवल 21 प्रतिशत है।

भारत में 2005-06 के बाद NFHS किया ही नहीं गया। नेपाल और बांग्लादेश हर तीन वर्षों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण करते हैं। अंत में 2014-2015 में NFHS करने का निर्णय लिया गया और आशा है कि इसके परिणाम 2015 के अंत तक सामने आ जाएंगे।

2005-2006 के बाद NFHS न होने के फलस्वरूप भारत में पोषण से सम्बंधित आकड़ों का अकाल पड़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा संसार भर में पोषण को ले कर प्रकाशित किए गए प्रतिवेदनों में भारत के बारे में अद्यतन जानकारी का पूरी तरह अभाव था और पुराने सर्वेक्षणों के आंकड़ों के आधार पर अत्यंत निराशाजनक तस्वीर उभर रही थी। इस बीच युनिसेफ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2013-14 में देश के सभी 29 राज्यों में 'बच्चों का एक त्वरित सर्वेक्षण' किया। इस सर्वेक्षण से काफी उत्साहजनक परिणाम मिले हैं।

इस रिपोर्ट के परिणामों को सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किए जाने के कारण इसकी कार्यविधि और आंकड़ों पर सवाल उठना स्वाभाविक है, किंतु आम तौर पर इन्हें विश्वसनीय माना जा रहा है क्योंकि कुछ पत्रिकाओं ने इस रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करके आंकड़ों का विश्लेषण कर लिया है। कुपोषित बच्चों का प्रतिशत, जो 2005-06 में 41.5 था, वह घटकर पिछले वर्ष (2013-14) में 30.7 तक पहुंच गया। कुपोषित बच्चों की संख्या में पिछले 25 वर्षों में यह सबसे बड़ी गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) ने भारत में कुपोषण की स्थिति को 'भयावह' से घटा कर 'गंभीर' कर दिया है। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में अधिक तेज़ी से तरक्की की है।

देश की पूरी आबादी में कुपोषित व्यक्तियों की संख्या, जो 2004-06 में 21.5 प्रतिशत थी, 2011-13 में घट कर 17 प्रतिशत हो गई है। कुपोषण के अन्य लक्षणों, जैसे रुद्ध विकास और कम वज़न होना, में भी उल्लेखनीय कमी आई है। राष्ट्रीय टीकाकरण की दर में वृद्धि हुई है, और खुले में शौच की प्रवृत्ति में कमी (55 प्रतिशत परिवारों से घट कर 45 प्रतिशत परिवार) आई है। खुले में शौच करना बच्चों में कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। आंत में रहने वाले परजीवी पचे हुए भोजन का एक बड़ा भाग चट कर जाते हैं और संक्रमित व्यक्ति में पोषण की कमी हो जाती है। मल के साथ निकले हुए इन परजीवियों के अंडों से अन्य बच्चों में परजीवियों का संक्रमण फैलता है।

IFPRI के अनुसार इस परिवर्तन के कारण हैं:

- सरकार द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना के दायरे में वृद्धि और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा योजना की निगरानी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ती पहुंच।
- मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार के अधिक अवसर और
- खाद्यान्नों पर मिलने वाले अनुदान की योजना का सुदृढ़ीकरण।

आशा की जानी चाहिए कि सरकार द्वारा शौचालय बनाने की मुहिम के कारण कुपोषण की समस्या हल करने में और अधिक मदद मिलेगी।

यदि इस रिपोर्ट को देश के राज्यों के संदर्भ में देखा

जाए तो मोटे तौर पर सामाजिक और स्वास्थ्य से सम्बंधित सूचकांक अपेक्षित पैटर्न के अनुसार ही दिखाई देते हैं। जिन राज्यों में औसत आय अधिक है, जो समुद्र के किनारे पर स्थित हैं, और दक्षिण में स्थित राज्यों में ये सूचकांक बेहतर हैं। केरल और तामिलनाडु के सूचकांक बहुत अच्छे हैं। कम औसत आय वाले और देश के उत्तर में स्थित राज्यों की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से कमज़ोर है। उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति सबसे खराब है। उत्तर-पूर्व में स्थित राज्यों में औसत आय कम होने के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है।

जिन राज्यों ने बालिकाओं और युवा माताओं के पोषण पर अधिक ध्यान दिया है वे कुपोषण के दुष्चक्र का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। जहां किशोरी बालिकाओं में वज़न और लम्बाई औसत से कम होती है वहां इस बात की संभावना अधिक होती है कि जन्म लेने वाले बच्चे कुपोषित होंगे। अतः बालिकाओं और महिलाओं के बेहतर पोषण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बाल कुपोषण में आई कमी की अच्छी खबर के बावजूद एक चिंताजनक पहलू यह है कि पूरे संसार में पांच वर्ष से कम आयु वाले कम वज़न के और रुद्ध विकसित बच्चों की संख्या भारत में सबसे अधिक है और 70 प्रतिशत बच्चे एनीमिया (रक्त की कमी) से पीड़ित हैं। ज़ाहिर है कि भारत को स्वास्थ्य और पोषण के संदर्भ में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ***(स्रोत फीचर्स)***